अरे देखो ! सड़क चोरी हो गई !!

सालाना कई
करोड़ रूपए सड़कों,
स्कूलों, ईमारतों के बनाने और
देख–रेख में खर्च होते हैं। वह पैसा
और किसी का नहीं, हमारा–आपका है।
सरकारी दस्तावेज़ों में, यह पैसा उन सभी कामों पर
खर्च हो चुका है जिनके लिए बंधा था – नौकरशाही का वेतन,
ठेकेदार की कमीशन, सीमेंट और रोड़ी, मज़दूरी . . . . . सभी की
लिखा–पढ़ी फाईलों में भरी है . . . . . लेकिन . . . . .

सड़क गायब है !

अभी तक, कोई सवाल करने पर जवाब मिलना बहुत कठिन था। किससे पूछें? क्या पूछें? क्या वे जवाब देंगे? कितने दिन में देंगे?

सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम 2002 के अनुसार हर नागरिक को सरकार और शासन से हर प्रकार की जानकारी लेने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग कीजिए। अपने स्कूलों, राशन, सड़कों इत्यादि की चोरी रोकिए !

CHRI
ACCESS TO INFORMATION PROGRAMME

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
एन-8, द्वितीय तल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016, भारत, दूरभाष : +91-11-2652 8152, 2685 0523
फैक्स : 91-11-2686 4688, ई-मेल : chriall@nda.vsnl.net.in वेबसाईट : www.humanrightsinitiative.org

कौन बना है करोड़पति ?

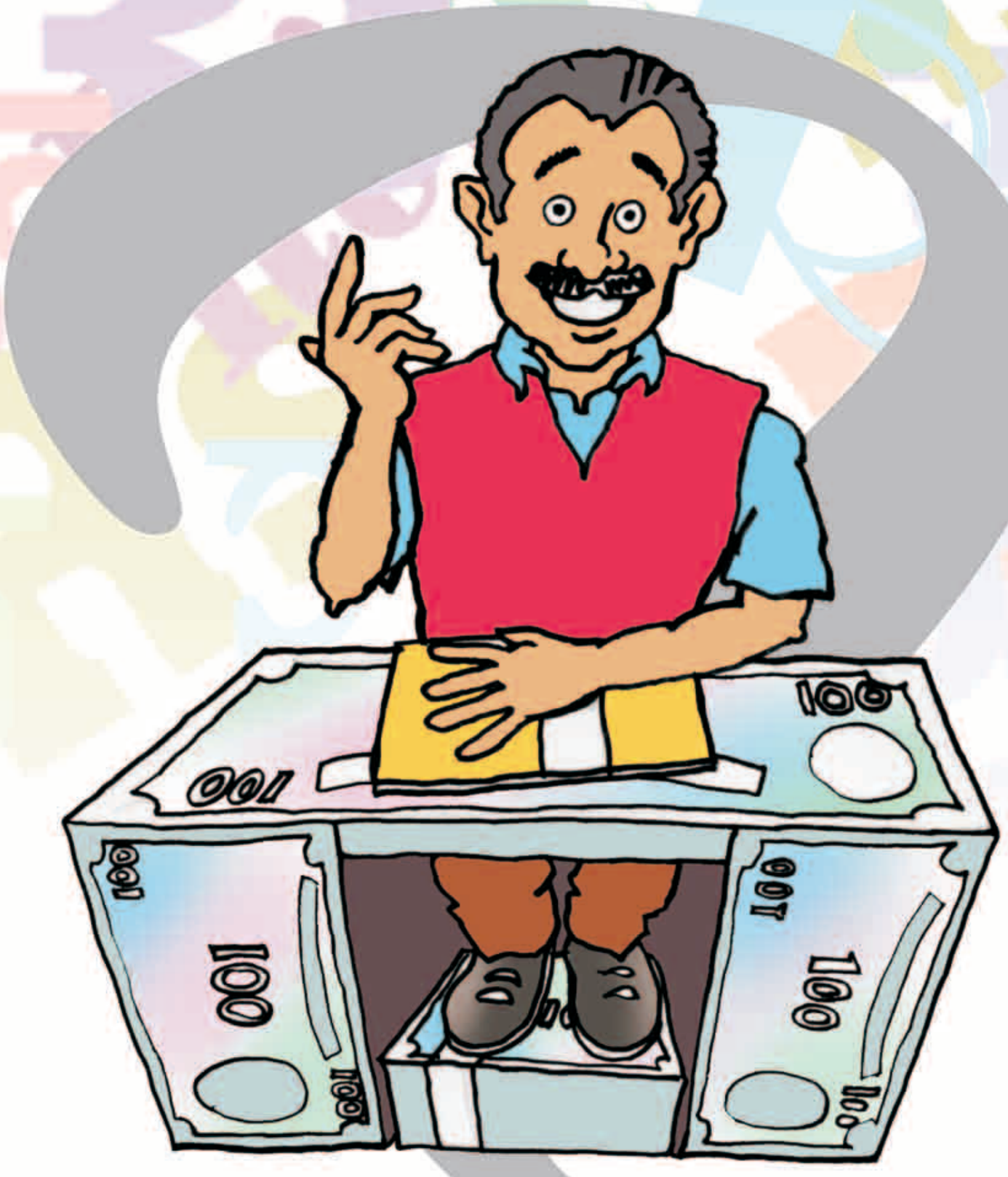

जनता के करोड़ों रुपयों को खेल समझ कर
भ्रष्टाचार से गायब किया जाता है।
और वह भी बिना जवाब दिए।

अपने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए।

जवाब मांगिए ! हिसाब मांगिए !

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशियेटिव
एन-8, द्वितीय तल, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016, भारत, दूरभाष : +91-11-2652 8152, 2685 0523
फैक्स : 91-11-2686 4688, ई-मेल : chriall@nda.vsnl.net.in वेबसाईट : www.humanrightsinitiative.org

CHRI
ACCESS TO INFORMATION PROGRAMME